KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

(1) प्रशासनिक शक्ति - Administrative power –

1.संघ के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर किया जायेगा। All actions of the executive of the Union will be taken in the name of the President.

2. समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। The consent of the President is necessary on all international treaty agreements.

3. अनु 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शाशन की घोषणा कर सकता है। Under Article 356, the President can declare rule in the states.

4 . संघ के महत्वपूर्ण पदों जैसे महान्यायवादी ,नियंत्रक महालेखा परीक्षक , उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश , निर्वाचन आयोग ,संघलोक सेवा आयोग , वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य , राजदूत ,उच्चायुक्त , केंदीय विश्वविद्यालय के कुलपति , राज्यपाल और प्रधानमंत्री सहित संघ के मंत्री परिषद् की नियुक्ति करता है

राष्ट्रपति स्वयं केन्द्रिय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है।

Important posts of the Union like Attorney General, Comptroller and Auditor General, Supreme Court and High Court judges, Election Commission, Union Public Service Commission, Chairman and members of the Finance Commission, Ambassadors, High Commissioners, Vice-Chancellors of Central Universities, Governors and Prime Ministers of the Council of Ministers of the Union. Makes appointment.

न्यायिक शक्ति - judicial power -

1. अनु 72 - राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति - President's power to grant pardon –

- किसी भी प्रकार के दंड के अपराध और अपराध सिद्धि से क्षमा कर सकेगा। Can pardon any kind of punishment from the offense and conviction.
- दंड को क्षमा , परिहार , लघुकरण , प्रवलिम्बन , विराम कर सकेगा। Will be able to forgive, avoid, reduce, postpone or stop the punishment.
- मृत्युदंड पर क्षमा दान दे सकेगा। Will be able to grant pardon on death sentence.
- सेना सर्वोच्च सेना पति होने के कारन सेना द्वारा दंडित ब्यक्ति को क्षमादान दे सकेगा। The Army, being the supreme commander, will be able to grant pardon to a person punished by the Army.
- इनके क्षमादान शक्ति की न्यायिक जाँच SC के द्वारा किया जा सकेगा। Judicial inquiry into their pardon power can be done by SC.

2 अनु 143 - राष्ट्रपति का सलाहकारी अधिकार - Advisory power of the President

ILU

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश से सलाह ले सकता है , लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। The President may seek advice from the Chief Justice of the Supreme Court, but the Chief Justice will not be bound to give advice.

यदि मामला संविधान लागु होने के पहले का हो तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य होगा। If the matter is before the implementation of the Constitution, the Chief Justice will be bound to give advice.

यदि मामला राजनैतिक हो तो सलाह नहीं देगा। Will not give advice if the matter is political.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING